भ्रष्टाचार पर प्रहार

विशेषांक

वर्ष : 1, अंक : 4

09 दिसंबर, 2019

अंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोध दिवस

26 मई, 2014 को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जब कैबिनेट की पहली बैठक में एसआईटी के गठन का निर्णय किया तो उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी मंशा जाहिर कर दी। यही वो घड़ी थी जब पीएम मोदी की अगुवाई में भारत ने तय कर लिया कि अब भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई नरमी नहीं बरती जाएगी।

भारत जैसे विशाल देश में नोटबंदी जैसा ऐतिहासिक फैसला करना कोई आसान काम नहीं था, लेकिन पीएम मोदी ने अपने दमखम से भ्रष्टाचारियों को खुली चुनौती दी। उनके इस साहसिक फैसले से पूरा विश्व आश्चर्यचकित था। पीएम मोदी भ्रष्टाचार के खिलाफ वैश्विक लड़ाई की मिसाल बन गए। उन्होंने देश की सवा सौ करोड़ जनता को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को भरोसा दिलाया कि अगर दृढ़ इच्छाशक्ति हो तो भ्रष्टाचार जैसी गंभीर बीमारी के खिलाफ भी निर्णायक जंग छेड़ी जा सकती है।

भ्रष्टाचारियों पर कानूनी शिकंजा हो या बेनामी संपत्ति कानून, डीबीटी हो या डिजिटल ट्रांजेक्शन – प्रधानमंत्री मोदी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ चौतरफा प्रहार किया। आज 09 दिसंबर को जब पूरा विश्व अंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोध दिवस मना रहा है, तो प्रधानमंत्री मोदी पूरी दुनिया के लिए उम्मीद की एक किरण बनकर सामने आए हैं।

PERFORM INDIA
National Movement for Developed India

मोदी राज में हुआ मुमकिन

- पहली बार कालेधन के खिलाफ एसआईटी का गठन
- पहली बार नोटबंदी का ऐतिहासिक फैसला
- पहली बार पूरे देश के लिए एक कर व्यवस्था 'जीएसटी' लागू
- पहली बार बेनामी संपत्ति जब्त करने का कानून लागू
- पहली बार स्विस बैंक ने दी भारतीय खाताधारकों की जानकारी
- पहली बार प्रत्यक्ष कर संग्रह बढ़कर 12 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचा
- पहली बार यूपीआई ट्रांजैक्शन की संख्या 2.7 अरब पहुंची
- पहली बार डीबीटी स्कीम से 1.4 लाख करोड़ रुपये की हुई बचत
- पहली बार ईज ऑफ डूइंग बिजेनस की रैंकिंग में 63वें स्थान पर पहुंचा भारत

भ्रष्टाचार हुआ कम, सर्वे ने लगायी मुहर

- वैश्विक भ्रष्टाचार सूचकांक, 2018 में भारत की रैंकिंग सुधरकर 78वें स्थान पर पहुंची, रिश्वतखोरी में 10 प्रतिशत की कमी
- ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में भारत 14 पायदान चढ़कर 63वें स्थान पर पहुंचा
- वैश्विक विश्वसनीयता सूचकांक में तीन अंक के सुधार के साथ भारत 52वें स्थान पर पहुंचा

वैश्विक भ्रष्टाचार सूचकांक

भारत की रैंकिंग में सुधार

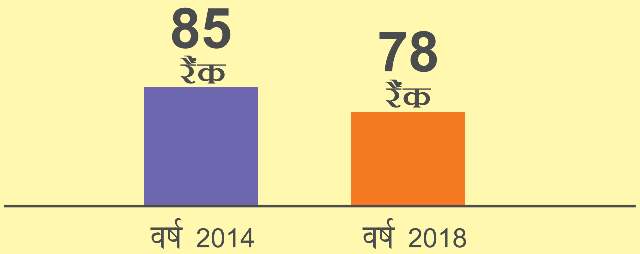

ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग

भारत की रैंकिंग में अप्रत्याशित उछाल

79 स्थानों का उछाल

भ्रष्टाचार मुक्त 'न्यू इंडिया' का संकल्प

"मैं हर जुल्म सहता रहूंगा, अवरोध सहता रहूंगा, लेकिन भ्रष्टाचार मुक्त भारत के सपने को साकार करके रहूंगा।"

"देश को लूटने और धोखा देने वाला हर व्यक्ति चाहे वह देश में हो या विदेश में, न्याय के समक्ष खड़ा किया जाएगा।"

"भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी। सरकार द्वारा उठाये गये कदमों से देश में आज ईमानदारी का उत्सव मनाया जा रहा है। जबकि बेईमानों के लिये सिर छुपाने की जगह नहीं मिल रही है।"

संकल्प से सिद्धि की दिशा में बड़े कदम

- कालेधन में लेन-देन खत्म करने के लिए जन धन योजना, नवंबर 2019 तक 37.5 करोड़ जन धन खाते खुले
- यूरिया की नीम कोटिंग से कालाबाजारी खत्म, देश में यूरिया के लिए खत्म हुए आंदोलन
- इनकम डिक्लेरेशन स्कीम 2016 की घोषणा, इसके तहत 65,250 करोड़ रुपये की संपत्ति घोषित
- गैर-राजपत्रित पदों के लिए इंटरव्यू खत्म होने से मनमाने फैसले पर लगा अंकुश, योग्यता को मिला सम्मान

नोटबंदी का ऐतिहासिक फैसला

- 8 नवंबर, 2016 को 500 और 1000 के पुराने नोट हटाने की ऐतिहासिक घोषणा
- शेल कंपनियों पर हुई सर्जिकल स्ट्राइक
- 3.5 लाख फर्जी कंपनियों का पंजीकरण रद्द
- 4.7 लाख से अधिक संदिग्ध लेन-देन की जानकारी मिली

नोटबंदी की बड़ी सफलता

- जाली नोटों पर लगी रोक
- 99 प्रतिशत कैश बैंकिंग सिस्टम में आए
- नक्सलियों, आतंकियों, हवाला कारोबारियों की टूटी कमर
- प्रॉपर्टी की कीमतों में 25 से 40 प्रतिशत तक आई कमी
- डिजिटल लेनदेन में बढ़ोतरी से लेस कैश हुई अर्थव्यवस्था
- आयकर रिटर्न भरने वालों की संख्या बढ़कर हुई दोगुनी
- साफ-सुथरी अर्थव्यवस्था की दिशा में बढ़े मजबूत कदम

भ्रष्टाचारियों पर कानूनी शिकंजा

- जीएसटी लागू होने से भ्रष्टाचार में आयी कमी, नवंबर 2019 में जीएसटी संग्रह एक लाख करोड़ रुपये से अधिक
- बेनामी संपत्ति लेन-देन रोकथाम कानून के तहत कार्रवाई तेज, 10 हजार करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति जब्त
- बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स बिल, 2019 पारित, निवेशकों को पोंजी स्कीमों से मिली सुरक्षा
- भ्रष्टाचार निरोधक (संशोधन) विधेयक-2018 के तहत रिश्वत लेने और देने वालों को 3 से 7 साल की कैद का प्रावधान
- भगोड़ा आर्थिक अपराध कानून के तहत आर्थिक अपराध कर विदेश भागने वालों की 20 हजार करोड़ की संपत्ति जब्त
- इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी कोड से बकाएदारों से कर्ज की वसूली में वृद्धि, बैंकों की आर्थिक स्थिति में हुआ सुधार
- रियल एस्टेट सेक्टर में भ्रष्टाचार रोकने और पारदर्शिता लाने के लिए RERA लागू, अब घर खरीदना हुआ सस्ता
- प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में संशोधन, विदेशों में जमा संपत्ति के बराबर भारत में संपत्ति जब्त करने का प्रावधान

भ्रष्टाचारियों के खिलाफ मुहिम

'ऑपरेशन क्लीन मनी'

- 'ऑपरेशन क्लीन मनी' वेबसाइट से कालेधन पर लगाम
- आयकर विभाग के छापों की रिपोर्ट्स वेबसाइट पर सार्वजनिक
- भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई और ईडी की छापेमारी

भ्रष्टाचार के आरोपी नेताओं की शामत

- INX मीडिया और पद के दुरुपयोग के मामले में पी. चिदंबरम 106 दिनों तक हिरासत में रहे
- नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप, दोनों जमानत पर
- मनी लॉन्डरिंग और भूमि सौदे में भ्रष्टाचार के मामले में ईडी ने रॉबर्ट वाड्रा से घंटों पूछताछ की
- हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपिंदर सिंह हुड्डा के खिलाफ भी गुरुग्राम में जमीन सौदे के मामले में जांच जारी
- बेनामी संपत्ति के मामले में लालू-राबड़ी और उनके बेटे पर मामला दर्ज, सीबीआई ने लालू के कई ठिकानों पर की छापेमारी

भ्रष्ट अफसरों-कर्मचारियों की खैर नहीं

- पीएमओ ने केंद्र सरकार के सभी विभागों से भ्रष्ट अधिकारियों की मांगी सूची
- मोदी सरकार में बीते 5 सालों में 300 से अधिक भ्रष्ट अफसर सेवामुक्त किए गए
- पैसे के लिए फाइल दबाने और देरी करने वाले कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई
- तीन वर्षों से अधिक समय से अहम पदों पर बैठे अधिकारियों के तबादले की रणनीति

भगोड़ों का बचना नामुमकिन

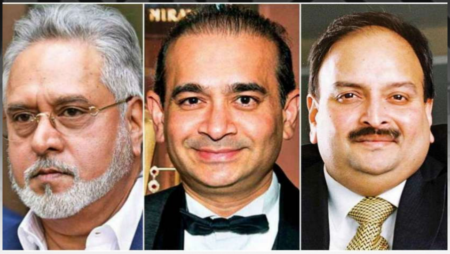

- मनी लांड्रिंग के आरोपों में घिरे गुजरात के संदेसरा ग्रुप की कुल 14,508 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त
- स्विट्जरलैंड में भगोड़े नीरव मोदी के चार बैंक एकाउंट सीज, करीब 300 करोड़ रुपये जब्त
- नीरव मोदी देश का दूसरा भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित, जब्त होंगी संपत्तियां
- भगोड़े विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चोकसी का होगा प्रत्यर्पण
- अगस्ता हेलिकॉप्टर सौदे के बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल समेत 11 भगोड़े अपराधियों को भारत लाने में मिली सफलता
- जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल और 100 करोड़ की धोखाधड़ी का आरोपी मॉन्टी चड्ढा एयरपोर्ट से गिरफ्तार

बैंक लोन देने में भ्रष्टाचार पर चोट

2015 से 2017 तक 3.38 लाख बैंक खाते बंद

करीब 10 हजार बैंक कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई

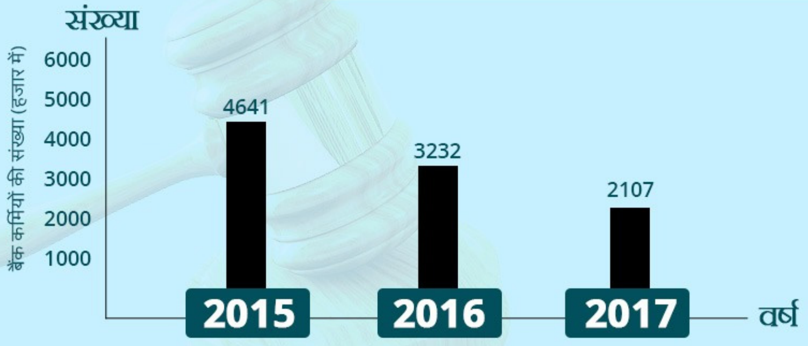

विदेशों में जमा कालेधन पर नजर

- भारत ने 154 देशों के साथ कालेधन से संबंधित दस्तावेज साझा करने का समझौता किया।
- भारत के साथ 100 से ज्यादा देशों ने 5 हजार दस्तावेजों को साझा किया।
- स्विस बैंक ने सितंबर, 2019 में भारतीय खाताधारकों के बारे में पहली बार जानकारी साझा की।
- स्विस बैंक में भारतीयों द्वारा जमा रकम 2018 में लगभग छह प्रतिशत घटकर 6,757 करोड़ रुपये हो गई।
- चीन के हांगझोउ में आयोजित जी-20 सम्मेलन में पीएम मोदी ने कालेधन के खिलाफ मदद के लिए देशों से अपील की।
- भारत ने सिंगापुर, साइप्रस और मॉरीशस से आने वाले कालेधन पर रोक के लिए डबल टैक्सेशन अवॉयडैंस एग्रीमेंट किया।
- भारत में विदेशी चंदे से चल रहे 14,800 एनजीओ का पंजीकरण रद्द किया गया।

कालेधन पर पीएम मोदी के प्रहार का असर

स्विस बैंक में जमा भारतीयों के कालेधन में आई गिरावट

13 पायदान फिसल कर 74वें स्थान पर पहुंचा भारत

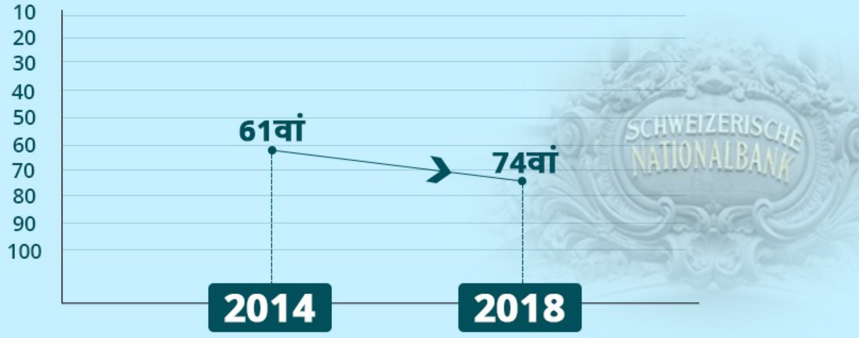

स्विस बैंक में धन जमा करने वाले देशों की सूची में भारत का स्थान

टेक्नोलॉजी से आई पारदर्शिता

कम हुआ कैश का प्रचलन

- यूपीआई ट्रांजैक्शन की संख्या 2.7 अरब पहुंची
- यूपीआई से कुल 4.6 ट्रिलियन रुपये का लेनदेन हुआ
- भीम ऐप से डिजिटल पेमेंट में अप्रत्याशित वृद्धि
- सरकारी विभागों में सामानों की ऑनलाइन खरीदारी
- ऑनलाइन हुई प्राकृतिक संसाधनों की नीलामी

डिजिटल भुगतान में जबर्दस्त वृद्धि

कीमत में यूपीआई लेन-देन

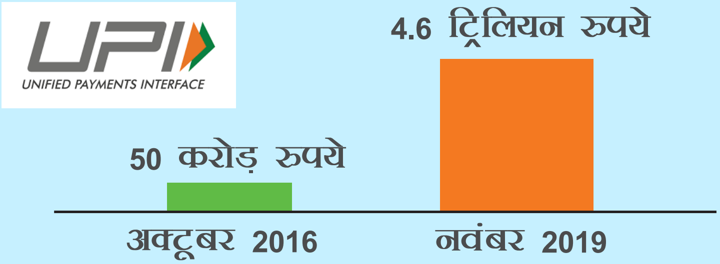

डीबीटी से भ्रष्टाचारियों पर प्रहार

- डीबीटी के दायरे में 56 मंत्रालयों की 436 योजनाएं
- रकम लाभान्वितों के बैंक खाते में सीधे ट्रांसफर
- 70.6 करोड़ लाभार्थियों को मिला फायदा

गेम चेंजर साबित हुआ डीबीटी

डीबीटी से हुई बचत

- 2014-15 - 14 हजार करोड़ रुपये
- 2019-20 - 1.4 लाख करोड़ रुपये

आधार से फर्जीवाड़े पर सीधी चोट

- पकड़ में आए 80 हजार से अधिक फर्जी शिक्षक
- मिड डे मील योजना में 4.40 लाख फर्जी छात्रों का पर्दाफाश
- 3 करोड़ फर्जी राशन कार्ड, 4.23 करोड़ फर्जी गैस कनेक्शन रद्द
- मनरेगा में एक करोड़ फर्जी जॉब कार्ड की पहचान

पारदर्शी बना राजनीतिक चंदा

- 2000 रुपये से अधिक के चंदे कैश में लेने पर पाबंदी
- बड़ी रकम चेक या डिजिटल माध्यम से लेना अनिवार्य
- राजनीतिक दलों के लिए रिटर्न फाइल करना हुआ जरूरी
- चंदा देने वाले के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड की शुरुआत